वित्त आयोग द्वारा शहरों को दिए जाने वाले अनुदान सीमित क्यों हैं: भारत के शहरी भविष्य के लिए एक चुनौती

UPSC प्रासंगिकता - प्रारंभिक परीक्षा: वित्त आयोग की भूमिका, शहरी स्थानीय निकाय और राजकोषीय हस्तांतरण, बद्ध (tied) बनाम अबद्ध (untied) अनुदान मुख्य परीक्षा - GS II: संघवाद, स्थानीय शासन, वित्त आयोग; GS III: शहरीकरण, बुनियादी ढांचा वित्तपोषण, राजकोषीय नीति

चर्चा में क्यों?

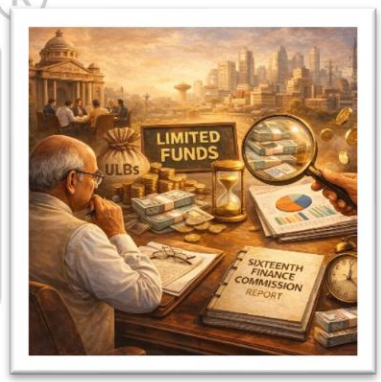

- हाल ही में, सोलहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को प्रदान किए गए सीमित वित्तीय समर्थन पर बहस तेज हो गई है।
- भारत के आर्थिक उत्पादन में शहरों की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी होने के बावजूद, शहरी सरकारों को राजकोषीय हस्तांतरण अपेक्षाकृत कम और अत्यधिक सशर्त बना हुआ है।
- यह शहरी शासन, राजकोषीय संघवाद और शहरों की दीर्घकालिक विकास की योजना बनाने की क्षमता पर चिंता पैदा करता है।

पृष्ठभूमि

- भारत के शहर आर्थिक विकास के प्राथमिक इंजन के रूप में उभरे हैं। शहरी क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 67% का योगदान देते हैं और सरकारी राजस्व का लगभग 90% उत्पन्न करते हैं।
- तीव्र शहरीकरण के साथ, 2031 तक शहरी आबादी लगभग 41% तक पहुँचने की उम्मीद है, जो 60 करोड़ लोगों से अधिक होगी।
- हालाँकि, इस बढ़ती आर्थिक और जनसांख्यिकीय भूमिका के बावजूद, शहरों की वित्तीय स्वायत्तता कमजोर बनी हुई है। स्थानीय सरकारें मजबूत स्थानीय कराधान प्रणालियों के बजाय अंतर-सरकारी हस्तांतरण (विशेष रूप से वित्त आयोग की सिफारिशों) पर भारी निर्भर हैं।

IAS PCS Institute
Result Mitra
रिजल्ट का साथी

आंकड़े क्या बताते हैं?

राजकोषीय आंकड़ों पर एक करीब से नज़र डालने से शहरी हस्तांतरण के सीमित पैमाने का पता चलता है।

1. 15वें वित्त आयोग के तहत अनुदान

- 15वें वित्त आयोग ने पांच वर्षों में शहरी स्थानीय निकायों के लिए ₹1.2–1.3 लाख करोड़ की सिफारिश की थी।
- इस अवधि के दौरान भारत की GDP: ₹200–210 लाख करोड़।
- GDP के हिस्से के रूप में शहरी अनुदान: लगभग **0.12–0.13%**।

2. 16वें वित्त आयोग के तहत अनुदान

- 16वें वित्त आयोग ने 2026 और 2031 के बीच शहरी स्थानीय निकायों के लिए लगभग ₹3.56 लाख करोड़ का प्रस्ताव दिया है, जो सालाना लगभग ₹75,000 करोड़ है।
- हालाँकि, भारत की अनुमानित GDP: लगभग ₹400 लाख करोड़।
- GDP का हिस्सा: अभी भी लगभग **0.13%** के आसपास।
- इस प्रकार, भले ही पूर्ण राशि (absolute amount) बढ़ गई हो, GDP का सापेक्ष हिस्सा स्थिर बना हुआ है।

3. प्रति व्यक्ति हस्तांतरण में गिरावट

- भारत की शहरी आबादी: 2020 में लगभग 47 करोड़, 2030 तक 60 करोड़ से अधिक होने की उम्मीद।
- जब राजकोषीय हस्तांतरण का समान स्तर बड़ी आबादी में वितरित किया जाता है, तो प्रति व्यक्ति अनुदान वास्तविक रूप में स्थिर रहता है या घट जाता है।

4. खर्च न की गई राशि (Unspent Funds)

- एक और चिंता आवंटित धन का कम उपयोग है।
- 15वें वित्त आयोग के तहत कुल स्थानीय निकाय अनुदान: ₹4.36 लाख करोड़।
- अनुमानित खर्च न की गई राशि: ₹90,000–95,000 करोड़।
- इसमें से शहरी हिस्सा: ₹30,000–35,000 करोड़।

IAS-PCS Institute
Result Mitra
रिजल्ट का साथी
@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

बद्ध अनुदान (Tied Grants) क्या हैं?

वित्त आयोग के हस्तांतरण का एक बड़ा हिस्सा "बद्ध अनुदान" होता है। ये विशिष्ट क्षेत्रों के लिए निर्धारित निधि हैं जैसे:

- जलापूर्ति
- स्वच्छता
- अपशिष्ट जल प्रबंधन

IAS-PCS Institute

यद्यपि ये क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, बद्ध अनुदान शहरों की राजकोषीय स्वायत्तता को सीमित करते हैं, क्योंकि स्थानीय सरकारें अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार धन आवंटित नहीं कर पाती हैं। 16वें वित्त आयोग के तहत, यह शर्त और भी मजबूत हो गई है। धन का एक हिस्सा अब प्रदर्शन-आधारित मानदंडों से जुड़ा है, जिनमें शामिल हैं:

- राजकोषीय अनुशासन में सुधार
- स्थानीय निकाय चुनावों का नियमित संचालन
- ऑडिट किए गए खातों का प्रकाशन
- राज्य वित्त आयोगों का गठन

Result Mitra
रिजल्ट का साथी

सशर्त अनुदान और राजस्व दबाव

वित्त आयोग ने 20% अनुदानों को प्रदर्शन की शर्तों से जोड़ा है, जिसमें 'स्वयं के स्रोत राजस्व' (OSR) को बढ़ाना शामिल है। शहरों से संपत्ति कर और सेवाओं के उपयोगकर्ता शुल्क के माध्यम से प्रति परिवार लगभग ₹1,200 उत्पन्न करने की अपेक्षा की जाती है।

@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

शहरी शासन में संघवाद की चिंताएं

- सिफारिशें राजकोषीय संघवाद के व्यापक मुद्दे भी उठाती हैं। एक उदाहरण 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में आसपास के गांवों के विलय के लिए ₹10,000 करोड़ का प्रोत्साहन है।
- चूंकि शहरी विकास **74वें संवैधानिक संशोधन** के तहत राज्य का विषय है, इसलिए क्षेत्रीय पुनर्गठन के लिए केंद्रीय प्रोत्साहन राज्य-स्तरीय शासन व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं।

उपेक्षित मुद्दा: उपकर (Cess) राजस्व

- केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए गए उपकर और अधिभार राजस्व से संबंधित एक और बड़ी चिंता है।
- उपकर संग्रह अब GDP का लगभग 2.2% (लगभग ₹8.8 लाख करोड़) है। ये राजस्व विभाज्य पूल (divisible pool) से बाहर हैं, जिसका अर्थ है कि इन्हें राज्यों या स्थानीय निकायों के साथ साझा नहीं किया जाता है।

आगे की राह: भारत के शहरों को सशक्त बनाना

1. **राजकोषीय हस्तांतरण में वृद्धि:** शहरी अनुदानों को GDP के हिस्से के रूप में विस्तारित किया जाना चाहिए।
2. **शर्तों (Conditionality) को कम करना:** अबद्ध अनुदानों (untied grants) पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए।
3. **स्थानीय राजस्व प्रणालियों को मजबूत करना:** शहरी सरकारों को संपत्ति कर प्रणाली और GIS-आधारित भूमि रिकॉर्ड का आधुनिकीकरण करना चाहिए।
4. **प्रशासनिक क्षमता में सुधार:** स्थानीय निकायों में तकनीकी और वित्तीय प्रबंधन क्षमता का निर्माण करना।
5. **उपकर प्रणाली में सुधार:** शहरी गतिविधियों से उत्पन्न उपकर राजस्व का एक हिस्सा शहरी बुनियादी ढांचे के लिए निर्धारित किया जा सकता है।

निष्कर्ष

भारत के शहर देश के आर्थिक परिवर्तन के केंद्र में हैं। शहरी सरकारों को प्रभावी ढंग से तेजी से शहरीकरण का प्रबंधन करने के लिए, राजकोषीय संघवाद को उन्हें अधिक संसाधन और निर्णय लेने का अधिकार देने की दिशा में विकसित होना चाहिए।

अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

IAS-PCS Institute
Result Mitra
रिजल्ट का साथी
@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

प्रश्न 1. *वित्त आयोग* के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है।
2. यह संघ और राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण की सिफारिश करता है।
3. यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है जो निरंतर कार्य करता है।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A. केवल 1 और 2

B. केवल 2 और 3

C. केवल 1 और 3

D. 1, 2 और 3

उत्तर: A

प्रश्न 2. निम्नलिखित में से कौन-से *वित्त आयोग* के कार्य हैं?

1. संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध प्राप्तियों के वितरण की सिफारिश करना।
2. राज्यों को दी जाने वाली अनुदान-सहायता (Grants-in-Aid) के सिद्धांत निर्धारित करना।
3. भारत के निर्वाचन आयोग के कार्यों की समीक्षा करना।
4. स्थानीय निकायों के संसाधनों को बढ़ाने के लिए राज्यों की समेकित निधि (Consolidated Fund) को सुदृढ़ करने के उपाय सुझाना।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

A. केवल 1 और 2

B. केवल 1, 2 और 4

C. केवल 2, 3 और 4

D. 1, 2, 3 और 4

उत्तर: B

UPSC मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: "आर्थिक विकास के इंजन होने के बावजूद, भारत के शहर गंभीर राजकोषीय बाधाओं का सामना करते हैं।" शहरी शासन को सुदृढ़ करने में *वित्त आयोग के अनुदानों* की भूमिका का परीक्षण कीजिए तथा इससे संबंधित चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। *(250 शब्द)*